

न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और न्यायाधीश रामेंद्र जैन के समक्ष

अत्तर सिंह और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी नंबर 10125 ऑफ 2015

सितंबर 03, 2015

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 226, 227-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1994-धारा 28, आयकर अधिनियम, 1961-धारा 194ए-प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज पर स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती- निर्धारिती द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति की परवाह किए बिना बढ़े हुए मुआवजे के ब्याज पर प्राप्ति के वर्ष में कर लगने योग्य होगा- कानून के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करके स्वीकार्य रिफंड का दावा कर सकता है।

यह निर्धारित किया गया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4 (बाद में "1961 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) निर्धारिती की आय पर प्रभार के आधार का प्रावधान करती है, जबकि लगाया गया कर या तो स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से एकत्र किया जाता है या निर्धारिती द्वारा सीधे भुगतान द्वारा। स्रोत पर कर कटौती, अधिनियम के अध्याय XVII के भाग बी के तहत निर्धारित "कर संग्रहण और वसूली" के तरीकों में से एक है। यह वास्तव में करदाता द्वारा देय कर की वसूली के लिए प्रावधान है और किसी भी तरह से कर के आरोपण या शुल्क को प्रभावित नहीं करता है। कुछ ही मामलों में ऐसे भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर स्रोत पर कर की कटौती करने और सरकारी खजाने में जमा करने का दायित्व डाला जाता है, लेकिन अधिनियम की धारा 199 के तहत, अधिनियम के अध्याय XVII के तहत कटौती की जाती है और भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार को निर्धारिती की ओर से भुगतान माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, टीडीएस राजस्व द्वारा कर का अनंतिम संग्रह है और हमेशा रिटर्न दाखिल करते समय अंतिम निर्धारण के अधीन होता है। याचिकाकर्ताओं को बढ़े हुए मुआवजे की राशि और उस पर ब्याज मिल गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा संलग्न अनुलग्नक पी-3 और पी-4 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज के तत्व पर कर की कटौती की गई है और इसलिए, यह अधिनियम की धारा 194ए के अंतर्गत आएगा जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा अन्य ब्याज से संबंधित है।

(पैरा 7)

आगे निर्धारित किया गया कि यह भी देखा जा सकता है कि 1961 अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में वित्त (सं 2.) अधिनियम, 2009 द्वारा 1.4.2010 को संशोधन किया गया था जिसका प्रभाव निम्नलिखित है :-

"viii) धारा 145ए के खंड (बी) में निर्दिष्ट मुआवजे पर या बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज के माध्यम से आय।"

इसके अलावा, 1961 अधिनियम की धारा 145ए में वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2009 द्वारा खंड (बी) सम्मिलित करके संशोधन भी किया गया था जो 1.4.2006 से लागू किया गया और जो निम्नानुसार है:-

"(बी) मुआवजे या बढ़े हुए मुआवजे पर एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त ब्याज, जैसा भी मामला हो, उस वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें यह प्राप्त है।"

उपरोक्त संशोधनों का संचयी प्रभाव यह होगा कि मुआवजे या बढ़े हुए मुआवजे की राशि पर ब्याज घटक प्राप्ति के वर्ष में कर के दायरे में आएगा भले ही निर्धारिती द्वारा लेखांकन की विधि का उपयोग किया जा रहा हो ।

(पैरा 8)

आगे निर्धारित किया गया कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, स्रोत पर कर

सही काटा गया है और याचिकाकर्ता कानून के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करके रिफंड का दावा कर सकते हैं, यदि कोई हो, और जो उन्हें स्वीकार्य है ।

(पैरा 16)

सुधीर अग्रवाल, वकील

याचिकाकर्ताओं के लिए।

ममता सिंगला तलवार, डीएजी, हरियाणा

सौरभ मागो, एएजी, हरियाणा के साथ।

न्यायधीश अजय कुमार मित्तल,

(1) यह आदेश 2015 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10125, 10135 और 10230 वाली तीन याचिकाओं का निपटारा करेगा। जैसा कि पक्षों के विद्वान वकील के अनुसार, इसमें समान मुद्दे शामिल हैं। संक्षिप्तता के लिए, तथ्यों को 2015 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10125 से निकाला जा रहा है।

(2) 2015 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10125 को याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की प्रार्थना करते हुए दायर किया गया है जो उत्तरदाताओं को उनकी अर्जित भूमि के मुआवजे से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में काटी गई राशि को जारी करने का निर्देश दे।

(3) वर्तमान याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य, जैसा कि उसमें बताया गया है, पर ध्यान दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता गांव सुल्तानपुर, तहसील फरुखनगर, जिला गुड़गांव की राजस्व संपत्ति के भीतर स्थित कृषि भूमि के मालिक थे। हरियाणा राज्य ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 11.1.2005 के माध्यम से गुड़गांव जिले में मानेसर-पलवल- कुंडली रोड के विकास और उपयोग के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उक्त भूमि का अधिग्रहण किया। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने दिनांक 10.5.2006 के फैसले के तहत 12.50 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ दायर किया और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव ने दिनांक 27.8.2012 के फैसले के तहत मुआवजे को `43,17,841/- प्रति एकड़ की दर से बढ़ा दिया। याचिकाकर्ताओं को फॉर्म-डी (क्रमशः अनुबंध पी-3 और पी-4) प्राप्त हुआ और उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ताओं की मुआवजा राशि से स्रोत पर कर काट लिया। याचिकाकर्ताओं के मुआवजे से टीडीएस के रूप में काटी गई राशि अधिनियम की धारा 28 के तहत दिए गए ब्याज के आधार पर निर्धारित मुआवजे का 20 प्रतिशत थी। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता कृषि भूमि के अधिग्रहण पर, अधिनियम की धारा 28 के तहत दिए गए ब्याज के कारण प्राप्त राशि के संबंध में टीडीएस की वापसी के हकदार थे। आयकर आयुक्त बनाम घनश्याम (एचयूएफ) <sup>1</sup>मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों और 2012 की सिविल रिवीजन संख्या 7740 ( जगमाल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) जिसका फैसला 18.7.2013 को हुआ (अनुलग्नक पी-5) में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता रखी गई थी।

<sup>1</sup> (2009) 315 ITR 1 (SC)

(5) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध यह दलील देते हुए किया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी अर्जित भूमि के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर प्रतिवादियों द्वारा टीडीएस सही तरीके से काटा गया था।

(6) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमें रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली।

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4 (बाद में इसे "1961 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) निर्धारिती की आय पर प्रभार के आधार का प्रावधान करती है जबकि लगाया गया कर या तो स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से या निर्धारिती द्वारा सीधे भुगतान के माध्यम से एकत्र किया गया। स्रोत पर कर कटौती अधिनियम के अध्याय XVII के भाग बी के तहत निर्धारित "कर संग्रहण और वसूली" के तरीकों में से एक है। यह वास्तव में, निर्धारितियों द्वारा देय कर की वसूली के लिए प्रावधान है और किसी भी तरह से कर के आरोपण या शुल्क को प्रभावित नहीं करता है। कुछ मामलों में ऐसे भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर स्रोत पर कर की कटौती करने और सरकारी खजाने में जमा करने का दायित्व डाला जाता है, लेकिन अधिनियम की धारा 199 के तहत, अधिनियम के अध्याय XVII के तहत की गई कटौती और केंद्र सरकार को भुगतान निर्धारिती की ओर से भुगतान के रूप में माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, टीडीएस राजस्व द्वारा कर का अनंतिम संग्रह है और हमेशा रिटर्न दाखिल करते समय अंतिम निर्धारण के अधीन होता है। याचिकाकर्ताओं को बड़े हुए मुआवजे की राशि और उस पर ब्याज मिल गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा संलग्न अनुलग्नक पी-3 और पी-4 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बड़े हुए मुआवजे पर ब्याज के तत्व पर कर की कटौती की गई है और इसलिए, यह अधिनियम की धारा 194ए के अंतर्गत आएगा जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा अन्य ब्याज से संबंधित है।

(8) यह भी देखा जा सकता है कि निम्नलिखित प्रभाव के लिए, वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2009 द्वारा 1961 अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में संशोधन 1.4.2010 से प्रभावी किया गया था:-

"viii) धारा 145ए के खंड (बी) में निर्दिष्ट मुआवजे पर या बड़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज के माध्यम से आय।" इसके अलावा, 1961 अधिनियम की धारा 145ए में वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधन करके खंड (बी) सम्मिलित करके 1.4.2010 नियमानुसार से लागू किया गया:

"(बी) मुआवजे या बढे हुए मुआवजे पर एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त ब्याज, जैसा भी मामला हो, उस वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें यह प्राप्त हुआ है।"

उपरोक्त संशोधनों का संचयी प्रभाव यह होगा कि मुआवजे या बढे हुए मुआवजे की राशि पर ब्याज घटक प्राप्त के वर्ष में कर के दायरे में आएगा, भले ही करदाता द्वारा लेखांकन की कोई भी विधि अपनाई गई हो।

(9) घनश्याम मामले (सुप्रा) में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर, जिस पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने भरोसा किया है, यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने मंजीत सिंह (एचयूएफ) कर्ता मंजीत सिंह बनाम भारत संघ और अन्य<sup>2</sup> में 14.1.2014 को निर्णय लिया जिसमें हममें से एक ( न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल) संदस्य है, ने इसी तरह के मुद्दे का निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निपटारा किया है और जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता घनश्याम के मामले (सुप्रा) से कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं :-

"12. विषय पर केस कानून की ओर ध्यान दिलाते हुए, अनिवार्य रूप से, डॉ. शामलाल नरूला बनाम सीआईटी, [1964] 53 आईटीआर 151 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जाता है, जिसने 1894 के अधिनियम के तहत ब्याज देने से संबंधित मुद्दे पर विचार किया था। 1894 के अधिनियम की धारा 28 के तहत ब्याज को उसकी धारा 34 के तहत ब्याज के समान माना जाता था क्योंकि दोनों को मालिक को देय राशि को वापस रखने के कारण माना जाता था और मुआवजे या कब्ज़ा बनाए रखने के अधिकार की हानि के लिए हर्जाना का हिस्सा नहीं बनता था । इस प्रकार यह देखा गया :-

"जैसा कि हमने पहले बताया है, जैसे ही कलेक्टर अवार्ड से पहले या बाद में भूमि पर कब्ज़ा कर लेता है, स्वामित्व पूरी तरह से सरकार में निहित हो जाता है और इसके बाद इस प्रकार अर्जित भूमि के मालिक के पास अर्जित भूमि पर कोई स्वामित्व या अधिकार नहीं रह जाता है। अवार्ड के तहत उसे दोनों अधिकारों का मुआवजा मिलता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 28 के तहत दिया गया ब्याज, बिल्कुल धारा 34 के अंतर्गत दिए गए ब्याज की तरह, कब्ज़ा बनाए रखने के अधिकार के नुकसान के लिए मुआवजा या क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता है, बल्कि मालिक को देय राशि को वापस रखने के लिए राज्य द्वारा देय मुआवजा है।"

<sup>2</sup> CWP No. 15506 of 2013

डॉ. शामलाल नरूला के मामले (सुप्रा) के सिद्धांत को बाद में टी.एन.के. गोविंदराजू चेट्टी बनाम सीआईटी, (1967) 66 आईटीआर 465, में एक फैसले में शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लागू किया गया था।

13. इसके अलावा अधिनियम की धारा 2(28ए) "ब्याज" को परिभाषित करती है और 1.6.1976 से प्रभावी होने के लिए इसे वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा शामिल किया गया था। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

“ब्याज” का अर्थ है उधार लिए गए किसी भी पैसे या किए गए ऋण (जमा, दावा या अन्य समान अधिकार या दायित्व सहित) के संबंध में किसी भी तरीके से देय ब्याज और इसमें कोई भी सेवा शुल्क या अन्य शुल्क, उधार लिए गए धन या किए गए ऋण के संबंध में या किसी क्रेडिट सुविधा के संबंध में जिसका उपयोग नहीं किया गया है, शामिल है।

अधिनियम की धारा 2 खंड (28 ए) में अभिव्यक्ति “ब्याज”, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'हित' शब्द के दायरे को विस्तृत करती है।

14. सर्वोच्च न्यायालय की अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बिक्रम सिंह बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, (1997) 224 आईटीआर 551 में डॉ. शामलाल नरूला के मामले (सुप्रा) को देखते हुए और अधिनियम की धारा 2(28ए) में "हित" की परिभाषा पर विचार करते हुए, यह दर्ज किया कि 1894 अधिनियम की धारा 28 के तहत ब्याज एक राजस्व प्राप्ति थी और कर योग्य है। इसे इस प्रकार रखा गया था:-

“विवाद अब अभिन्न नहीं रह गया है। इस प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा डॉ. शामलाल नरूला बनाम आयकर आयुक्त, जम्मू [51 आईटीआर 151] मामले में विस्तार से विचार किया गया था। उसमें, न्यायाधीश के. सुब्बा राव, जैसा कि वह उस समय थे, ने प्रिवी काउंसिल और अन्य सभी मामलों द्वारा निर्धारित "हित" की अवधारणा पर पहले के मामले के कानून पर विचार किया था और पृष्ठ 158 पर यह निर्धारित किया था: "ऐसे मामले में जहां स्वामित्व राज्य के पास जाता है, उसके बाद प्रदान किए गए वैधानिक ब्याज को केवल उस लाभ का प्रतिनिधित्व करने के रूप में माना जा सकता है जो भूमि के मालिक ने कमाया होता यदि उसने उस पैसे का उपयोग किया होता या नुकसान जो उसे उठाना पड़ा क्योंकि उसके पास उसका उपयोग नहीं था। शब्द के किसी भी अर्थ में मालिक के कब्जे को बनाए रखने के अधिकार के लिए इसे क्षति या मुआवजे के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास अधिनियम की धारा 16 या 17 में कब्जा ले लेने के बाद अपने पास कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है। हम यह निर्धारित करते हैं की

अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दिया गया विधिक ब्याज, मुआवजा राशि के भुगतान को देरी से करने के लिए दिया गया ब्याज है और आए कर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य राजस्व प्राप्ति है। “

कानून की इस स्थिति को टीएमके गोविंदराजू चेट्टी बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास [66 आईटीआर 465], राम राय और अन्य बनाम सीआईटी, आंध्र प्रदेश [181 आईटीआर 400] और के.एस. कृष्णा राव बनाम सीआईटी, ए.पी. [181 आईटीआर 408] के मामले में इस न्यायालय द्वारा लगातार दोहराया गया है। इस प्रकार न्यायिक घोषणाओं की श्रृंखला के अनुसार, यह स्थापित कानून है कि मुआवजे के विलंबित भुगतान पर प्राप्त ब्याज एक राजस्व प्राप्ति है और आय कर के योग्य है। यह सच है कि धारा 2(28ए) में "ब्याज" की परिभाषा में संशोधन करते समय ब्याज को किसी भी तरह से उधार लिए गए पैसे या किए गए ऋण के संबंध में किसी भी तरह से देय ब्याज के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसमें जमा, दावा या अन्य समान अधिकार या दायित्व शामिल हैं और इसमें उधार लिए गए धन या किए गए ऋण के संबंध में या किसी क्रेडिट सुविधा के संबंध में कोई भी सेवा, शुल्क या अन्य शुल्क शामिल है जिसका उपयोग नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि अधिनियम के उद्देश्य के लिए "हित" शब्द की व्याख्या समावेशी परिभाषा द्वारा की गई थी। शाब्दिक निर्माण इस निष्कर्ष पर ले जा सकता है कि उधार लिए गए किसी भी पैसे या किए गए ऋण या प्रगणित अनुरूप लेनदेन के संबंध में किसी भी तरह से प्राप्त या देय ब्याज को ब्याज माना जाएगा। इसे बोर्ड द्वारा यहां पहले उल्लिखित परिपत्र में समझाया गया था। लेकिन सवाल यह है: क्या अधिग्रहण अधिनियम के तहत अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर विलंबित भुगतान पर ब्याज आयकर के योग्य नहीं होगा? ऐसा देखा गया है कि इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि यह एक राजस्व प्राप्ति है। "ब्याज" की संशोधित परिभाषा का उद्देश्य मुआवजे के विलंबित भुगतान पर ब्याज की राजस्व प्राप्ति को कर योग्यता से बाहर करना नहीं था। एक बार जब इसे राजस्व प्राप्ति माना जाता है, तो आवश्यक रूप से, जब तक कि अधिनियम के उचित प्रावधानों के तहत छूट न हो, राजस्व प्राप्ति कर के दायरे में आती है। संशोधन केवल कर के दायरे में, ब्याज की परिभाषा के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त आय को इसके कर दायरे में लाने के लिए है। इसका मतलब यह होगा कि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28 या 31 के तहत निर्धारित मुआवजे के विलंबित भुगतान पर आय के रूप में प्राप्त ब्याज एक कर योग्य घटना है।“

(15) अब, हम घनश्याम (एचयूएफ) के मामले (सुप्रा) में शीर्ष न्यायालय के फैसले की ओर रुख करते हैं, जिसके आधार पर निर्धारिती के विद्वान वकील ने सीआईटी बनाम बीर सिंह, आईटीए नंबर 209 ऑफ 2004 में इस न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसका

27.10.2010 को फैसला सुनाया जहां इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना है कि 1894 अधिनियम की धारा 28 के तहत मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर अदालत द्वारा दिए गए ब्याज का तत्व, प्राप्ति के वर्ष में धारा 56 के तहत 'अन्य स्रोतों से आय' के रूप में कराधान के लिए आता है।

16. घनश्याम (एचयूएफ) के मामले (सुप्रा) में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था:-

“संक्षेप में, ब्याज मुआवजे से अलग है। हालाँकि, 1894 अधिनियम की धारा 28 के तहत अतिरिक्त राशि पर भुगतान किया गया ब्याज उस व्यक्ति के दावे पर निर्भर करता है जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई है जबकि धारा 34 के तहत ब्याज भुगतान करने में देरी के लिए है। इस मामले पर निर्णय लेते समय इस महत्वपूर्ण अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। धारा 28 के तहत ब्याज मुआवजे की राशि का हिस्सा है जबकि धारा 34 के तहत ब्याज केवल मुआवजे की राशि निर्धारित होने के बाद भुगतान करने में देरी के लिए है। धारा 28 के तहत ब्याज भूमि के बढ़े हुए मूल्य का एक हिस्सा है, जो धारा 34 के तहत ब्याज के भुगतान के मामले में नहीं है।”

17. डॉ. शाम लाल नरूला, टी.एन.के.गोविंदराजा चेट्टी, अमरजीत सिंह, सुंदर, बिक्रम सिंह के मामले (सुप्रा), रमा बाई बनाम सीआईटी (1990) 181 आईटीआर 400 और के.एस.कृष्णा

राव बनाम सीआईटी, (1990) 181 आईटीआर 408 में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक घोषणाओं के मद्देनजर, निर्धारिती ऊपर उद्धृत उपरोक्त टिप्पणियों से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।”

(10) निर्धारिती द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की विशेष अनुमति (सी) संख्या 34642/2014 के तरीके से अपील की गई जिस को सुप्रीम कोर्ट ने 18.12.2014 को निम्नलिखित आदेश के साथ खारिज कर दिया था:

“याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना और प्रासंगिक सामग्री का अवलोकन किया।

हमें हस्तक्षेप के लिए कोई कानूनी और वैध आधार नहीं मिला। विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं।”

(11) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2009 द्वारा 1.4.2009 से किए गए संशोधनों को भी ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं को घनश्याम के मामले (सुप्रा) में फैसले से कोई फायदा नहीं मिल सकता है।



(12) अधिनियम की धारा 28 के तहत ब्याज की कर योग्यता के मुद्दे की जांच करते हुए, आयकर आयुक्त बनाम बीर सिंह (एचयूएफ), 2004 के आईटीए नंबर 209 में 27.10.2010 को फैसला सुनाया गया, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा यह माना गया कि धारा के तहत बढ़े हुए मुआवजे पर अदालत द्वारा दिया गया ब्याज अधिनियम की धारा 28 में प्राप्ति के वर्ष में अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर लगाया जाना था। इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने आयकर आयुक्त, पंचकुला बनाम प्रेम सिंह के मामले में 16.12.2010 को इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए फैसला सुनाया, जैसा कि नीचे दर्ज किया गया है:-

"11. मामले के इस दृष्टिकोण में, धारा 28 के तहत बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज घटक पर अधिनियम की धारा 56 के तहत कर लगाया जा सकता है, भले ही मुआवजे को कृषि आय के रूप में माना जाता है और अधिनियम की धारा 45(सी) के तहत कवर नहीं किया जाता है। इस प्रकार हम राजस्व के पक्ष में प्रश्नों का उत्तर देते हैं और अपने दिनांक 5.7.2010 के आदेश को तदनुसार संशोधित करते हैं। बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज की राशि प्राप्ति के वर्ष में करयोग्य मानी जाती है, भले ही बढ़े हुए मुआवजे के अवॉर्ड के खिलाफ कार्यवाही लंबित हो।

(13) जगमाल सिंह के मामले (सुप्रा) (अनुलग्नक पी-5) में विद्वान एकल न्यायाधीश का फैसला जिस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया है, उपरोक्त घोषणाओं के विपरीत होने के कारण इसे कानूनी प्रावधानों की सही व्याख्या नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार, इसे खारिज कर दिया गया है।

(14) इसके अलावा, इस न्यायालय ने सारती बनाम हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड और अन्य के मामले में, 2011 के सीडब्ल्यूपी संख्या 9739 में इसी तरह की परिस्थितियाँ में स्रोत पर कर कटौती के मुद्दे से निपटने के लिए 30.5.2011 को निर्णय लिया, निम्नानुसार दर्ज की गई:-

"8. इस न्यायालय ने, 2004 की आयकर अपील संख्या 209 में, जिसका निर्णय 27.10.2010 को लिया गया था (आयकर आयुक्त फरीदाबाद बनाम बीर सिंह (एचयूएफ) बल्लागढ़) में माना था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 के तहत निर्धारिती को ब्याज का भुगतान (संक्षिप्तता के लिए, "1894 अधिनियम") अधिग्रहीत भूमि के संबंध में मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर किया गया था और यह अधिनियम की धारा 56 के तहत "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में कराधान के लिए आता है और नकदी लेखांकन की प्रणाली के तहत प्राप्ति के वर्ष में कर के लिए पात्र है। यह भी देखा गया है कि जहां निर्धारिती किसी विशिष्ट पद्धति को अपनाकर खातों की

किताबें नहीं रख रहा है, उसे लेखांकन की नकद प्रणाली माना जाएगा। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त ब्याज बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान में देरी के कारण था और इसलिए, 1894 अधिनियम की धारा 28 के तहत आएगा। ऐसा भुगतान कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के स्वभाव को स्वीकार नहीं कर सकता है और, इस प्रकार, अधिनियम के तहत छूट नहीं दी गई है। एक बार ऐसा होने पर, स्रोत पर कर भुगतानकर्ता द्वारा सही तरीके से काटा गया था।“

(15) उपरोक्त को देखते हुए स्रोत पर कर सही कट गया है और याचिकाकर्ता रिफंड मांग सकते हैं, यदि कोई हो और जो उन्हें कानून के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करके स्वीकार्य है।

(16) रिट याचिकाएं उपरोक्त टिप्पणियों के साथ खारिज कर दी जाती हैं।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा